

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001



F.No.29-6(1)/2008-Reports

9th April, 2009

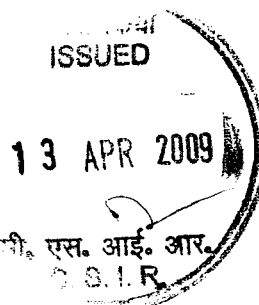
From:

The Financial Adviser
Council of Scientific & Industrial Research

To

The Heads of all National Labs/Instts.

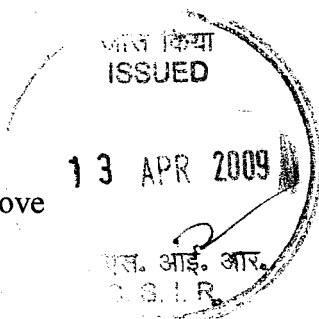
Sir,



I am to enclose herewith a copy of Office Memorandum No.1/84/09-MC dated 17th March, 2009 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Monitoring Cell on the subject "Eighty-fourth Report on Action Taken on 54th report of PAC (14th Lok Sabha) relating to Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations(2005-06)" for further necessary action and strict compliance.

Yours faithfully,

(RAJESH PAREEK)
FINANCE & ACCOUNTS OFFICER



Encl : as above

Copy to:

1. Sr.Dy.FAs/Dy.FAs/Sr.COFA/COFA of National Labs/Instts
2. Sr.DS/DS/Sr.COAs/COAs/AOs of all National Labs/Instts.
3. FAOs of all National Labs/Instts.
4. All Sections/Division of CSIR Hqrs.
5. Head, IT Division with the request to make this circular available to the website.

No.1/84/09-MC
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
MONITORING CELL

Room No. 229, Second Floor, B-Wing,
Loknayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi-110003 the 17th March, 2009

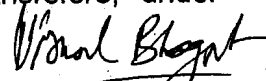
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Eighty-fourth Report on action taken on 54th report of PAC (14th Lok Sabha) relating to "Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations (2005-06)".

The undersigned is directed to refer to Public Accounts Committee's recommendations contained in Para 8 of its 84th Report (14th Lok Sabha) on the subject noted above, the contents of which are reproduced below:

"The Committee are constrained to point out that despite repeated assurances given by the various Ministries/Departments including the Ministry of Finance (Department of Expenditure) for timely submission of Action Taken Notes, most of the Ministries/Departments concerned, barring the Department of Fertilizers and Ministry of Labour & Employment, have not furnished the Action Taken Notes with the prescribed time limit of six months. The Ministry of finance (Department of Expenditure), which is the nodal Ministry for monitoring the submission of timely Action Taken Notes have also delayed furnishing Action Taken Notes pertaining to them by more than 11 months. The Committee are surprised to note that no extension was sought by the Ministries of Finance, Defence, Mines and Department of Posts when they were not in a position to furnish replies with the stipulated time. The Committee regret to observe that delays in furnishing Action Taken Notes have become a recurring phenomenon. Further not seeking extension by the Ministries tantamount to under mining the Parliamentary authority. The Committee hope that in case of expected delays experienced by the Ministries/Departments due to genuine difficulties, they would promptly approach the Committee for extension of time explaining inter-alia the precise reasons therefore. The Committee also desire that the Ministry of finance in consultation with Comptroller and Auditor General (C&AG) of India should also put in place a Centralized Computerized Monitoring System to check the status of the submission of Action Taken Notes on the lines of the one which is stated to be under operation for explanatory Notes."

All the Ministries/Departments are requested to note the recommendations for strict compliance and furnish the ATNs within stipulated time. In case of expected delays experienced by the Ministries/Departments due to genuine difficulties, they should promptly approach the Committee for extension of time explaining inter-alia the precise reasons therefore, under information to Monitoring Cell.


(N.K. BHAGAT)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA
TELE: 24626829

Ms. Shiela Sangwan,
JS & Financial Advisor,
Ministry/Department of CSIR,
Anusandhan Bhavan, Rft. Mg,
New Delhi

सी. एस. आर.
रिपोर्ट अनुपात
हाथी नं 666
दिनांक... 19.3.09

अति तत्काल
लोक लेखा समिति सामग्री

नं. 1/84/09-एमसी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
निगरानी कक्ष

कमरा नं.229, द्वितीय तल, बी-विंग,
लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक 17 मार्च, 2009

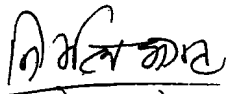
कार्यालय ज्ञापन

विषय: "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2005-06) से अधिक व्यय" से संबंधित लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 54वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी चौरासीवां प्रतिवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर 84वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के पैरा 8 जिसकी सामग्री नीचे प्रस्तुत की गई है, में अंतर्विष्ट लोक लेखा समिति की सिफारिशों का हवाला देने का निदेश हुआ है:

"समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वित्त मंत्रालयों (व्यय विभाग) सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पण समय पर प्रस्तुत करने हेतु बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उर्वरक विभाग और श्रम और रोजगार मंत्रालय को छोड़कर अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने छः माह की निर्धारित समय सीमा में की गई कार्यवाही टिप्पण उपलब्ध नहीं कराए हैं। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), जो की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय से प्रस्तुत करने की निगरानी हेतु नोडल मंत्रालय है, ने भी उनसे संबंधित की गई कार्यवाही टिप्पण उपलब्ध कराने में 11 माह से अधिक का विलंब किया है। समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि वित्त, रक्षा, खान मंत्रालयों और डाक विभाग ने अधिक समय नहीं मांगा जबकि वे निर्धारित समय में उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। समिति यह देखकर खेद व्यक्त करती है कि की गई कार्यवाही टिप्पण प्रस्तुत करने में बार-बार विलंब हो रहा है। इसके अतिरिक्त मंत्रालयों द्वारा और समय की मांग न किया जाना संसद के प्राधिकार को कम करने के समान है। समिति आशा करती है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा वास्तविक कठिनाइयों के कारण होने वाले अपेक्षित विलंब के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ तत्संबंधी कारण स्पष्ट करते हुए समिति से और समय दिए जाने की मांग करनी चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि वित्त मंत्रालय को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) के परामर्श से व्याख्यात्मक टिप्पण हेतु पहले से विद्यमान प्रणाली के आधार पर की गई कार्यवाही टिप्पण प्रस्तुत किए जाने की स्थिति की निगरानी हेतु केंद्रीकृत कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।"

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन सिफारिशों को दृढ़ता से अनुपालन के लिए नोट करें और की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दें। वास्तविक कठिनाइयों के कारण महसूस किए जाने वाले अपेक्षित विलम्बों के मामले में अन्य बातों के साथ ही ठीक-ठीक कारणों का उल्लेख करते हुए समय बढ़ाए जाने के लिए समिति से तत्काल सम्पर्क करें और इसकी सूचना निगरानी कक्ष को दें।


(एन. के. भगत)

अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 24626829

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।